अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स (श्री अन्न) वर्षः 74वी गणतंत्र दिवस परेडः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मिलेट्स (श्रीअन्न) प्रदर्शित किये

कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के विशेष आकर्षण के रूप में आईसीएआर की झांकी में 'अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष 2023' विषय पर प्रकाश डाला गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की झांकी द्वारा गुरुवार, 26 जनवरी को हाल ही में पुनर्निर्मित कर्तव्य पथ पर आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस परेड के विशेष आकर्षणों में से एक अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 थीम थी। आईसीएआर की झांकी में लहलहाती ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी और सांवा की फसल दिखाई गई। झांकी के आगे ट्रैक्टर पर मिलेट्स के दानों से रंगोली बनाई गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में, 72 देशों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का समर्थन किया कि 2023 मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा। इसके बाद, यूएनजीए ने 2023 को मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, जो उस तारीख को आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष की जी20 अध्यक्षता भारत में आयोजित की जा रही है, जो इस विशिष्ट झांकी के महत्व को और भी बढ़ा देती है। लंबे समय से वैश्विक और क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा 20 राष्ट्रों के इस समूह की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक रही है।

भारत का मिलेट्स व्यापार और उत्पादन

2.5 मिलियन हेक्टेयर उत्पादन क्षेत्र और 15 प्रतिशत से अधिक की बाजार हिस्सेदारी के साथ, भारत को मिलेट उत्पादन में एक वैश्विक नेता के रूप में मान्यता प्राप्त है। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जो श्री अन्नों का उत्पादन करते हैं। 2021–2022 के दौरान, भारत ने 34.32 मिलियन डॉलर मूल्य के मिलेट्स उत्पादों का निर्यात किया। 2019–2020 में 28.5 मिलियन डॉलर की तुलना में भारत ने 2020–2021 में 26.97 मिलियन डॉलर के मिलेट्स का निर्यात किया। संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, मिस्र, ट्यूनीशिया, यमन, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के शीर्ष मिलेट्स निर्यातक देश हैं।

छोटे बीज वाली घास जिन्हें अक्सर ''पोषक–अनाज'' कहा जाता है, को मिलेट्स माना जाता है। उनमें से कुछ हैं ज्वार (सोरघम), बाजरा (पर्ल मिलेट), रागी (फिंगर मिलेट), कुटकी (लिटिल मिलेट), काकुन (फॉक्स मिलेट), चीना (प्रोसो मिलेट), सावा (बार्नयार्ड मिलेट), और कोदो मिलेट (कोदोन)। वर्तमान में, मिलेट को ''सुपर फूड'' के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष घोषित किया है।

श्री तोमर ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 'अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष' विषय पर बैठक की अध्यक्षता की।

मिलेट और अन्य पोषक अनाजों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार देश और विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकारों के साथ, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डी.ए.एफ.डब्ल्यू.) तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) के समन्वय से पोषक अनाजों को बढ़ावा देंगे। यह बात केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 'अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष' विषय पर संपन्न हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष (आईवाईओएम) घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन प्राप्त

था और संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने मार्च, 2021 में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष–2023 की कार्य योजना उत्पादन, खपत, निर्यात, ब्रांडिंग आदि को बढ़ाने की रणनीतियों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री अन्नों को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना भी शुरू की है।

प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के तहत सरकार ने 31 मार्च, 2021 को वर्ष 2021–2022 से 2026–27 तक सात साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ क्रियान्वयन के लिए ''खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना'' नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी।

इस योजना के प्राथमिक उद्देश्यों में वैश्विक खाद्य निर्माण चौंपियनों के निर्माण में सहायता करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना शामिल है। योजना के तहत सहायता प्रदान करने के लिए उच्च विकास क्षमता वाले विशिष्ट खाद्य उत्पाद खंडों की पहचान की गई है। इनमें मिलेट्स आधारित उत्पादों सहित पकाने के लिए तैयार/खाने के लिए तैयार (आरटीसी/आरटीई) खाद्य पदार्थ शामिल हैं। श्री तोमर ने कहा कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति और सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा सचिव, डेयर की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी गठित की गई है, जो न्यूट्री–अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यक्रमों और नीतियों की निगरानी करेगी।

सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष–2023 के रन–अप में 'सात सूत्र' (थीम) विकसित किए हैं, जो संबंधित मंत्रालय/विभागों द्वारा शुरू किए जाएंगे। ये हैं– उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग), पोषण और स्वास्थ्य लाभ (स्वास्थ्य मंत्रालय/एफएसएसएआई), मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण और रेसिपी विकास (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और पर्यटन मंत्रालय), उद्यमिता/स्टार्ट–अप/सामूहिक विकास (वाणिज्य और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग), ब्रांडिंग लेबलिंग सहित जागरूकता निर्माण और प्रमोशन (सभी मंत्रालय), इंटरनेशनल आउटरीच (वाणिज्य और विदेश मंत्रालय) और मुख्यधारा के लिए नीतिगत हस्तक्षेप (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)। श्री अन्न प्रोटीन, फाइबर, खनिज, आयरन, कैल्शियम के समृद्ध स्रोत हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। भारत मिलेट का एक प्रमुख उत्पादक देश है, जो एशिया के उत्पादन का 80 प्रतिशत और वैश्विक उत्पादन का 20 प्रतिशत है। भारत की मिलेट्स की औसत उपज (1239 किग्रा/हेक्टेयर) वैश्विक औसत उपज 1229 किग्रा/हेक्टेयर से भी अधिक है। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख श्री अन्न फसलें और उनके उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा हैं, पर्ल मिलेट (बाजरा) – 61 प्रतिशत हिस्सा, ज्वार (सोरघम) – 27 प्रतिशत, और फिंगर मिलेट (मंडुआ/रागी)–10 प्रतिशत है।

सरकार ने श्री अन्नों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। घरेलू और वैश्विक मांग उत्पन्न करने और लोगों को पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए 2018 में श्री अन्न का राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। बाजरा के पोषण मूल्य को देखते हुए सरकार ने श्री अन्न को अप्रैल, 2018 में पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित भी किया। पोषण मिशन अभियान के तहत मिलेट्स शामिल भी किए गए। मिलेट्स मूल्य श्रृंखला में 500 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जबकि भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान ने आर.के.वी.वाई.–आर.ए.एफ.टी.ए.ए.आर. के तहत 250 स्टार्टअप को पोषित किया है। 66 से अधिक स्टार्टअप्स को 6.2 करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए गए हैं जबकि लगभग 25 स्टार्टअप्स को और फंडिंग के लिए मंजूरी दी गई है।

सलाहकार समिति की बैठक में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, सुश्री शोभा करंदलाजे और श्री कैलाश चौधरी ने भाग लिया। बैठक में भाग लेने वालों में संसद सदस्य श्री असित कुमार मल, श्री बेलाना चंद्रशेखर, श्रीमती जसकौर मीणा, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्रीमती रमा देवी, सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग, श्री मनोज आहूजा, श्री एस रामालिंगम, श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल और श्री राम शकल थे। सचिव, डेयर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, डॉ. त्रिलोचन महापात्र तथा मंत्रालय व आईसीएआर के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी विचार–विमर्श में भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष (आई.वाई.ओ.एम. 2023) घोषित किया।

जागरूकता पैदा करने और मिलेट्स के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के उद्देश्य से, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में, भारत सरकार के प्रस्ताव पर, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष घोषित किया। खाद्य एवं कृषि संगठन अन्य प्रासंगिक हितधारकों के सहयोग से इस वर्ष को मनाने के लिए प्रमुख एजेंसी है। मिलेट्स कम से कम निवेश के साथ शुष्क भूमि पर बढ़ सकते हैं और जलवायु में परिवर्तन के लिए लचीले होते हैं। इसलिए वे देशों के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने और आयातित अनाज पर निर्भरता कम करने के लिए एक आदर्श समाधान हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 मिलेट्स के पोषण और

स्वास्थ्य लाभों व प्रतिकूल और बदलती जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रत्यक्ष नीतिगत ध्यान देने का अवसर होगा। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए नए स्थायी बाजार के अवसर प्रदान करने की उनकी क्षमता को उजागर करते हुए, यह वर्ष श्री अन्नों के स्थायी उत्पादन को भी बढ़ावा देगा।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र ने मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है और मिलेट्स उत्पादन के लिए वार्षिक लक्ष्य तय किया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) कार्यक्रम के तहत न्यूट्री–अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए एनएफएसएम–न्यूट्री अनाज को 14 राज्यों के 212 जिलों में लागू किया जा रहा है। ज्योति ने कहा कि एनएफएसएम के तहत, किसानों को राज्य सरकारों के माध्यम से हस्तक्षेप के लिए किसानों को सहायता दी जाती है जैसे कि प्रथाओं के बेहतर पैकेज पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, उच्च उपज वाली किस्मों (एचवाईवी)/हाइब्रिड बीजों का वितरण, उन्नत कृषि मशीनरी/संसाधन संरक्षण मशीनरी/उपकरण, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, पौध संरक्षण उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारण, प्रसंस्करण और कटाई के बाद के उपकरण, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि। उन्होंने कहा कि मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को प्रौद्योगिकी बैक स्टॉपिंग और विषय वस्तु विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की देखरेख में किसानों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। मंत्री ने कहा, ''अनुसंधान संगठनों को अनुसंधान परियोजनाओं के लिए समर्थन दिया जाता है जो खाद्य फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।'' ज्योति ने कहा कि राज्य सरकारें संबंधित राज्यों की राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–कृषि और संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई–रफ्तार) के तहत बाजरा की खेती को भी बढ़ावा दे सकती हैं।

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि प्राकृतिक खेती को कृषि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए,

श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है, जिसमें लागत कम होती है और उत्पाद का अधिक मूल्य मिलता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने षनिवार को कहा कि सरकार कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक खेती को शामिल करेगी। तोमर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यषाला में बोल रहे थे। तोमर ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है, जिसमें लागत कम होती है और उपज का अधिक मूल्य मिलता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अब कृषि शिक्षा का हिस्सा होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही प्राकृतिक खेती के तरीकों को कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास कर रही है। तोमर ने उस दौर को याद किया जब भारत की आबादी की तुलना में खाद्यान्न की कमी थी।

उन्होंने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम अतिरिक्त खाद्यान्न उगाते हैं," उन्होंने कहा। तोमर ने कहा कि स्वस्थ मन, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ कृषि और स्वस्थ मनुष्य के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती पूर्णता की खेती है। इसमें पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है। एक आम किसान के लिए प्राकृतिक खेती में काम करने के लिए देशी गाय का गोबर और गोमूत्र पर्याप्त है। अगर देश प्राकृतिक खेती को अपनाता है, तो गाय सड़कों पर नहीं दिखेंगी, लेकिन उनका सही इस्तेमाल होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गुजरात के डांग जिले में शत प्रतिशत प्राकृतिक खेती की जा रही है. हिमाचल में भी किसान इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश ने 5,000 गांवों में इसकी योजना बनाई है। तोमर ने कहा कि हमारे देश में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बताया कि रासायनिक खेती से मिट्टी की उर्वरता कमजोर होती है, अनुकूल बैक्टीरिया का क्षय होता है। देश को 25 साल बाद आने वाले संकट से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती पद्धति को फिर से शुरू किया है और इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, जबकि करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) के माध्यम से हर साल 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक 2.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान के एवज में 1.24 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।